बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 63 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 16 दिसम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा का असर, हाईकोर्ट ने हाइब्रिड मोड में मामले की सुनवाई करने को कहा

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में होने के कारण दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को बार के सदस्यों और खुद पेश होने वाली पार्टियों को सलाह दी कि जहां भी सुविधाजनक हो, उनके सामने लिस्टेड मामलों में हाइब्रिड तरीके से पेश हों। रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि यदि सुविधाजनक हो, तो बार के सदस्य/खुद पेश होने वाली पार्टियां अदालतों के सामने लिस्टेड अपने मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से हाइब्रिड तरीके से पेश हो सकते हैं। यह सलाह ऐसे समय आई है जब दिल्ली की हवा की गुणवत्ता गंभीर कैटेगरी में बनी रही।

प्रियंका गांधी से क्यों मिलने पहुंच गए प्रशांत किशोर? दिल्ली में 2 घंटे तक गुपचुप मुलाकात के क्या है मायने?

नई दिल्ली । चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में जन सूरज पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं में छा गए हैं। किशोर ने हाल ही में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक बंद कमरे में बैठक की, जिससे राजनीतिक गलियारों में नई अटकलें लगने लगी हैं। प्रशांत किशोर का गांधी परिवार से रिश्ता नया नहीं है। 2021 में जेडीयू से अलग होने के बाद, किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी को पुनर्जीवित करने की योजना प्रस्तुत की थी। अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के आवास पर हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। उस समय किशोर कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें सशक्त कार्य समूह का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया था। सूत्रों ने बताया कि बैठक लगभग दो घंटे तक चली, हालांकि दोनों पक्षों ने इसके महत्व को कम आंकने की कोशिश की है और इसे एक नियमित बातचीत बताया है। किशोर की जन सूरज पार्टी की करारी चुनावी हार के बाद यह मुलाकात हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट जीतने में नाकाम रही और 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस का

प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा और उसने 61 सीटों में से सिर्फ छह सीटें जीतीं। किशोर की प्रियंका गांधी से बातचीत ने उनकी राजनीतिक रणनीति में संभावित बदलाव को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब उन्होंने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस से स्पष्ट दूरी बनाए रखी थी। किशोर का कांग्रेस नेतृत्व से जुड़ाव 2021 से शुरू हुआ, जब उन्होंने जनता दल (यूनाइटेड) छोड़ दिया था। अप्रैल 2022 में, किशोर ने सोनिया गांधी के आवास पर आयोजित एक बैठक में कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष एक विस्तृत पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी उपस्थित थे। उस समय, किशोर को पार्टी के प्रस्तावित सशक्त कार्य समूह में भूमिका की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि कांग्रेस को सीमित संगठनात्मक भूमिकाओं के बजाय संरचनात्मक सुधारों और निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता है। इस असहमति के कारण दोनों के रास्ते अलग हो गए, और किशोर बाद में पार्टी के एक मुखर आलोचक के रूप में उभरे। हालांकि, प्रियंका गांधी के साथ चुनाव के बाद हुई मुलाकात से संकेत मिलता है कि संवाद के रास्ते खुले हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि चर्चा बिहार की राजनीति, विपक्ष की रणनीति और भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं पर केंद्रित थी। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ये बातचीत किसी औपचारिक सहयोग में तब्दील हो पाएगी या नहीं।

अमित शाह के हाथ में रिमोट कंट्रोल..., नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर कांग्रेस ने कसा तंज

नई दिल्ली । कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को बिहार के पांच बार के विधायक नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि नबीन सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष बनकर रह जाएंगे, जबकि पार्टी की असली बागडोर अमित शाह के हाथों में होगी। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष की नियुक्ति बिना चुनाव के की गई है और उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष का पदनाम दिया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा का एक सांकेतिक शब्द है, जिसका अर्थ है कि गैर-कार्यकारी केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा अध्यक्ष को नियंत्रित करते हैं, न कि गृह मंत्रालय का संचालन करते हैं। खेड़ा ने आगे कहा कि रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथों में ही रहेगा, जैसा कि पहले होता आया है। नड्डा जी भाजपा अध्यक्ष के रूप में घूमते-फिरते थे, लेकिन प्रमुख निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेते थे, और अब भी ऐसा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने पार्टी मुख्यालय में अपने आधिकारिक दायित्वों का कार्यभार संभाला। यह उनके राजनीतिक करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अपनी यात्रा से पहले एएनआई से बात करते हुए, नबीन ने बिहार और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया और राष्ट्रीय भूमिका तक पहुंचने का श्रेय उनके आशीर्वाद को दिया। उन्होंने कहा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से ही यह संभव हो पा रहा है।

नबीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन को भी स्वीकार किया, जिन्होंने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी। दिल्ली रवाना होने से पहले, बिहार के मंत्री ने आशीर्वाद लेने के लिए पटना के महावीर मंदिर का दौरा किया। उन्होंने अपने पिता, दिवंगत वरिष्ठ भाजपा नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की प्रतिमा पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर नवीन ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को न केवल सीखने और काम करने के लिए बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया है।

प्रधानमंत्री के खिलाफ नारों के लिए देश से माफी मांगें कांग्रेस नेता - लोकसभा में रीजीजू

नई दिल्ली । कांग्रेस की रविवार को आयोजित एक रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ लगाए गए नारों को लेकर सत्तापक्ष के विरोध के कारण सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के करीब पांच मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगनी चाहिए। सदन की बैठक 11 बजे शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुछ पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना दी और सभा ने कुछ पल मौन रखकर दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का निर्देश दिया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने रविवार को यहां आयोजित कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा, ''कल कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी की कब्र खोदने की बात कही गई। यह इस देश के लिए बहुत दुखद है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। पूरी कांग्रेस पार्टी...पूरा का पूरा नेतृत्व उस रैली में मौजूद था और प्रधानमंत्री मोदी जी की कब्र खोदने का नारा इन्होंने लगाया।''उन्होंने कहा कि इस देश के लिए इससे यादा शर्मनाक, इससे यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि देश के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोगों के नेता, विश्व के सबसे प्रसिद्ध और सबसे मजबूत नेता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। रीजीजू ने कहा, ''2014 में एक भाजपा सांसद ने एक गलत शब्द का इस्तेमाल विपक्ष के लिए किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उस सांसद को तुरंत माफी मांगने को कहा और उन्होंने माफी मांगी।'' केंद्रीय मंत्री ने कहा, '' सब इस सदन में चुनकर आए हैं। हम विरोधी हैं, दुश्मन नहीं। हम इस सदन में लोगों के चुने गए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं।''उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस के कुछ सदस्य भी अपने स्थान पर खड़े होकर शोर-शराब कर रहे थे। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। रविवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित कई वीडियो में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर रामलीला मैदान में विपक्षी पार्टी की रैली में जाते समय 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' के नारे लगाते हुए सुना गया।

लोकसभा 2024 के बाद अब 2026 की तैयारी, बीजेपी ने पीयूष गोयल और बैजयंत पांडा को सौंपी बड़ी राज्यों की जिम्मेदारी

नई दिल्ली ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को वाणिय एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को तमिलनाडु का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया, जबकि भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को असम राय का प्रभारी बनाया गया है। दोनों रायों में 2026 में चुनाव होंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए विधि एवं न्याय एवं संसदीय कार्य राय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल और नागरिक उड्डयन एवं सहकारिता राय मंत्री मुरलीधर मोहोल को सह-निर्वाचित नियुक्त किया गया है, जबकि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता और विधायक सुनील कुमार शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री दर्शना बेन जरदोश को असम का सह-निर्वाचित बनाया गया है। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के एक दिन बाद, बिहार के मंत्री नितिन नबीन ने सोमवार को पटना में अपने पिता, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं का निरंतर मार्गदर्शन किया है और वे अपने पिता के आशीर्वाद से आगे की यात्रा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने यहां महावीर मंदिर में जाकर प्रार्थना भी की। राय भाजपा अध्यक्ष और बिहार मंत्री दिलीप जायसवाल भी उनके साथ मंदिर गए थे। नवीन ने कहा कि मैं अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं। मैंने महावीर मंदिर में दर्शन भी किए, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। मेरे पिता के आशीर्वाद से ही मैं इन 20 वर्षों में इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मैं अपने पिता के आशीर्वाद से ही आगे की यात्रा शुरू करूंगा। अपने पिता और भाजपा के दर्शन को याद करते हुए 45 वर्षीय नवीन ने कहा, वे कहते हैं कि हमेशा देश को पहले और खुद को दूसरे स्थान पर रखो, और हमने इसी सोच के साथ काम करने की पूरी कोशिश की है। नवीन ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद लेने मंदिर जा रहा हूं... पार्टी ने हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी हैं और उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। मैं पार्टी नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पांच बार के विधायक नवीन आज बाद में भाजपा मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण संकट पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा उचतम न्यायालय

नई दिल्ली । उचतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर से संबंधित याचिका पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पामचोली की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह की दलीलों पर गौर किया, जो न्याय मित्र के रूप में न्यायालय की सहायता कर रही हैं। सिंह ने कहा कि यद्यपि निवारक उपाय मौजूद हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा अधिकारियों द्वारा उपायों का खराब कार्यान्वयन है। सिंह ने कहा कि जब तक यह अदालत कोई निर्देश नहीं देती, अधिकारी पहले से मौजूद प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। इस पर सीजेआई ने कहा, ''यह मामला बुधवार को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आएगा। इस पर सुनवाई होगी।'' एक अन्य वकील ने बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे से जुड़े एक आवेदन का हवाला देते हुए कहा कि पहले के आदेशों के बावजूद स्कूल बाहरी खेल गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। न्याय मित्र ने यह भी कहा, ''इस अदालत के आदेश के बावजूद स्कूलों ने इन खेल गतिविधियों को आयोजित करने के तरीके खोज लिए हैं... ये गतिविधियां हो रही हैं। सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) एक बार फिर इस अदालत के आदेश का हवाला दे रहा है।''सीजेआई ने कहा, ''हम समस्या को जानते हैं और हम ऐसे आदेश पारित करेंगे जिनका पालन किया जा सके।

ख़बरों के आगे-पीछे - क़ुरआन ख़्वानी और गीता पाठ, मक़सद क्या?

लगता है सौ साल पुराना वाक़या दोहराया जा रहा है, जब देश में विभाजन की शुरुआत राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आधार पर हुई थी, जो अंततः भौगोलिक विभाजन में बदल गई। इस समय भी वही होता दिख रहा है। धर्म की राजनीति मंदिर और मस्जिद से आगे बढ़ कर धर्मग्रंथों तक पहुंच गई है। अयोध्या में नवनिर्मित राममंदिर पर ध्वज फहराए जाने के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। इसमें बड़ी संख्या में दूर दूर से मुस्लिम ईंटें लेकर पहुंचे। राममंदिर के लिए भी एक समय ऐसे ही शिलापूजन हुआ था। हुमायूं कबीर ने शिलान्यास के लिए छह दिसंबर का दिन चुना, जिस दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। इसके अगले दिन कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पांच लाख लोगों ने गीता पाठ किया। इसमें राज्यपाल सीवी आनंद बोस, रामदेव और धीरेंद्र शास्त्री भी शामिल हुए। ऐसा लग रहा है कि यह एक बार का शो नहीं था। अब पूरे देश में इस तरह के काम होने जा रहे हैं। हुमायूं कबीर ने कहा है कि वे फरवरी में कुरआन ख्वानी' कराएंगे, जिसमें एक लाख लोगों खाना खिलाया जाएगा। उधर हैदराबाद में 28 दिसंबर को किराअत' यानी कुरआन का पाठ कराया जाएगा। इसके लिए मस्जिद-ए-कुतुबशाही में कुरान पाठ का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। मुस्लिम समूहों की इस तैयारी के बरक्स वहां भी गीता पाठ या किसी धार्मिक आयोजन की संभावना है। सो, कोलकाता से हैदराबाद तक कुरआन और गीता का पाठ होगा। सब अपने-अपने हिसाब से भोज कराएंगे और इस तरह पाला खिंचता जाएगा। सौ साल पहले में विभाजन की शुरुआत ऐसे ही हुई थी।

गरीब ओडिशा में विधायकों के ऐश

ओडिशा में वह हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नवीन पटनायक ने अपने करीब 25 साल के राज में विधायकों के वेतन-भत्तों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की थी। जिस समय सारे देश के विधायक और सांसद भी अपने वेतन-भत्तों आदि में बढ़ोतरी कर रहे थे उस समय भी ओडिशा में विधायकों के वेतन-भत्तों में कछुआ चाल से बढ़ोतरी हुई। लेकिन उनकी सरकार जाते ही राज्य में बहुत कुछ बदलने लगा। बीजू जनता दल को हरा कर सत्ता में आई भाजपा ने एक बार में विधायकों के वेतन में तीन गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। अभी तक ओडिशा के विधायकों को एक लाख रुपया महीना मिलता था, जिसे बढ़ा कर 3.45 लाख रुपया कर दिया गया है। यह देश में विधायकों को मिलने वाला सबसे बड़ा सैलेरी पैकेज है, जबकि ओडिशा की गिनती देश के गरीब राज्यों में होती है।

बहरहाल मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधायकों की पेंशन में भी लगभग तीन गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके लिए लाया गया विधेयक बीते मंगलवार को विधानसभा में पारित हो गया। मुख्यमंत्री को 3.74 लाख रुपया महीना मिलेगा। गौरतलब है कि ओडिशा में पिछले सात साल से वेतन नहीं बढ़ाया गया था। उससे पहले में नवीन पटनायक ने मामूली बढ़ोतरी की थी। अब एक ही बार में भाजपा की मोहन चरण माझी की सरकार ने सारी कसर पूरी कर दी है।

तीन जजों के खिलाफ महाभियोग

संसद में अरसे बाद जजों के खिलाफ अभियोग के प्रस्ताव आए हैं। एक प्रस्ताव आया तो उसका सिलसिला ही शुरू हो गया। बड़ी जद्दोजहद के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकार की ओर से लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पेश हुआ। इस पर स्पीकर ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद संसद में उस पर चर्चा होगी और अगर उससे पहले जस्टिस वर्मा का इस्तीफा नहीं होता है तो उनको महाभियोग के जरिए हटाया जाएगा। वे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं। उनके घर से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के आरोप लगे हैं। इस बीच अब विपक्ष की ओर से मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के जज जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश हुआ है। उन पर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने वाले फैसले देने का आरोप डीएमके, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी आदि ने लगाए हैं। उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अधिकारियों को वहां एक दरगाह के पास स्थित स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति दी है। उनके खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर 107 सांसदों ने दस्तखत किए हैं। महाभियोग के लिए 50 सांसदों के दस्तखत की जरूरत होती है। डीएमके नेता कनिमोझी के मुताबिक स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा है कि वे इस पर विचार करेंगे। इसी तरह सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ राज्यसभा के 50 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि यह प्रस्ताव दस्तखत में गड़बड़ी की वजह से विवाद में फंस गया है।

शिंदे की पार्टी को भाजपा बचाएगी

आमतौर पर भाजपा पर दूसरी पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगता है और कहा जाता है कि वह अपनी विरोधी पार्टी को ही नहीं बल्कि अपनी सहयोगी पार्टी को तोड़ने में भी कोई संकोच नहीं बरतती। लेकिन यह पहला मौका है जब उसे अपनी एक सहयोगी पार्टी को टूटने से बचाना पड़ेगा।

मामला महाराष्ट्र का है, जहां भाजपा के साथ सरकार में शामिल एकनाथ शिंदे की शिव सेना पर टूट का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 का है। भाजपा ने अकेले 132 सीटें जीती हैं और शिव सेना व एनसीपी को मिला कर उसके पास प्रचंड बहुमत है। बताया जा रहा है कि भाजपा की ओर से लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि उसका अपने दम पर बहुमत हो जाए। लेकिन क्या यह बहुमत शिंदे की शिव सेना को तोड़ कर बनेगा? कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की शिंदे के साथ खटपट चल रही है लेकिन शिंदे को दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं का समर्थन हासिल है।

मुश्किल यह है कि अगर भाजपा अपने को मजबूत करने के लिए शिव सेना को तोड़ती है तो फिर उसका मौजूदा विशाल बहुमत नहीं रह पाएगा। क्योंकि शिंदे के कुछ विधायक टूट कर भाजपा में जाएंगे तो बचे हुए विधायक और पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ चली जाएगी। फिर उद्धव ठाकरे की शिव सेना का रिवाइवल हो जाएगा। भाजपा ऐसा नहीं होने दे सकती है। इसलिए एकनाथ शिंदे की शिव सेना का वजूद बचा रहेगा।

सिद्धू की राजनीतिक पारी समाप्ति की ओर

नवजोत सिंह सिद्धू का राजनीतिक करिअर मुश्किल में है। वे न तो सांसद है और न विधायक और न कांग्रेस में उनके पास कोई पद है। कांग्रेस चाहती तो उनके जैसे ऊर्जावान नेता का प्रदेश में प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी। रवनीत सिंह बिट्टू के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तीनों की राजनीति के लिए एक प्रभावशाली सिख चेहरे की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस ने नवजोत सिद्धू को बर्फ में डाल दिया, जिसे पंजाबी में खुड्डे लाइन लगाना कहते हैं। सिद्धू भाजपा में थे तो तीन बार सांसद बने। भाजपा से उनकी पत्नी विधायक भी बनीं। कांग्रेस में गए तो सिद्धू एक बार विधायक ही बन पाए है और नवजोत कौर का राजनीतिक करिअर भी डूब गया। अब नवजोत कौर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा बना कर चुनाव लड़े तो उसको फायदा होगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह जोड़ दिया कि उनके पास पांच सौ करोड़ रुपए नहीं हैं। अगर होते तो वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन जाते। उनके इस बयान पर विवाद छिड़ा है। उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है।

भाजपा पूछ रही है कि पांच सौ करोड़ रुपए का बैग कांग्रेस में किसको देना होता कि सिद्धू मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाते? कांग्रेस में माना जा रहा है कि नवजोत कौर के बयान के बाद पार्टी में सिद्धू के लिए बची खुची संभावना भी समाप्त हो गई है।

सम्पादकीय...

शोले पर भी संसद में बहस हो जाये सरकार-जी!

वंदे मातरम पर संसद में दस घंटे की बहस हुई। वंदे मातरम की एक सौ पचासवीं वर्षगांठ जो थी। साथ ही मैंने कहीं यह भी पढ़ा है कि राज्य सभा में कुछ और नारों के साथ वंदे मातरम का नारा लगाने पर भी रोक लगा दी गई है। लगता है राज्य सभा में अब बस एक ही नारा लगा सकते हैं और वह है मोदी! मोदी! उस पर शायद कहीं कोई रोक नहीं है। हां तो वंदे मातरम पर दस घंटे बहस हुई। बहस यह हुई कि वंदे मातरम गीत के मात्र पहले दो पैरा जिन लोगों ने राष्ट्रगीत के रूप में रखे वे लोग मुस्लिम परस्त थे, देशद्रोही थे। मुस्लिम तुष्टिकरण करना चाहते थे। क्योंकि वे लोग भाजपाई नहीं थे, आरएसएस के नहीं थे, हिन्दू महासभा के नहीं थे तो वे लोग देशद्रोही थे। जो काम भी बीजेपी, आरएसएस, हिन्दू महासभा या जनसंघ ने नहीं किया है, वह देशद्रोह है, ऐसा पिछले दस सालों से स्थापित किया जा रहा है। चलो मान लेते हैं, आप जो कहते हैं, वह ठीक है। गुरुवर रविंद्र नाथ टैगोर ने, नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने, लौह पुरुष सरदार पटेल ने और जवाहर लाल नेहरू ने जो किया, ठीक नहीं किया। राष्ट्रगीत में वंदे मातरम के पहले दो पैराग्राफ ही रख कर ठीक नहीं किया। पूरे के पूरे छह छंद रखने चाहिए थे। ये सारे लोग देशद्रोही थे। देशभक्त तो सिर्फ भाजपाई है और उनके पूर्वज हैं। यह जो संसद में वंदे मातरम पर बहस हुई, उसमें हमारे सदन अध्यक्ष को एक शर्त रखनी चाहिए थी। जो लोग वंदे मातरम में छह के छह छंद रखना चाहते हैं वे बिना पर्चियों के सहारे सारे छंद मुंह जुबानी सुनाएंगे। टेलीप्रोम्पटर वीर को भी बहस की शुरुआत वंदे मातरम के पूरे छह छंद सुना कर करनी चाहिए थी। दल के बाकी सदस्य भी पहले पूरा वंदे मातरम सुनाते और फिर अपनी बात रखते। मजा आ जाता सचमुच। संसद के मौजूदा शीत सत्र में अभी पांच दिन बाकी हैं। कुछ बेकार की बहसें नहीं होंगी तो लोग बेरोजगारी पर बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे, रुपये की गिरती कीमत पर बात करेंगे। इंडिगो संकट पर बात करेंगे, चीन के बढ़ते प्रभुत्व पर बात करेंगे और अमेरिकी टैरिफ पर बात करेंगे। दिल्ली के मौसम के मजे और प्रदूषण की बात करेंगे। काम की बातें न करके बेकार की बात करेंगे। और सांसद बेकार की बातों में न उलझें, उसके लिए जरूरी है कि संसद के हर सत्र में दो चार इसी तरह की बहस हों। ऐसी बहस हो कि पूरे देश का ध्यान उसकी ओर खिंच जाये। एक बहस तो मैं सुझा सकता हूं। मेरी गारंटी है लोग उसे ध्यान से सुनेंगे और अपने सारे दुख दर्द, जो सरकार जी के ग्यारहवें साल के शासन काल के बाद भी बाकी हैं, भुला देंगे। सरकार जी शोले फ़िल्म पर बहस करवा दें। देख लेना, कितनी सफल होगी। शोले फ़िल्म पर बहस हो इसकी कई वजह हैं। पहली तो इस वर्ष शोले फ़िल्म के रिलीज़ के पचास वर्ष पूरे हुए हैं। दूसरी, शोले एक कल्ट फ़िल्म है जिसने अपार सफलता प्राप्त की थी। लोगों को वंदे मातरम का सुजलाम सुफलाम याद हो या ना हो, शोले फ़िल्म के कई डायलॉग अभी तक याद हैं। और इस फ़िल्म के बहाने नेहरू और कांग्रेस, दोनों को घसीटा जा सकता है। आप कहेंगे कैसे, तो मैं समझाता हूं। पहली बात तो गब्बर सिंह का जन्म 1950 में हुआ था और शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी जी का जन्म 1947 में। पर नेहरू ने शोले फ़िल्म को अपने जीवन काल में नहीं बनने दिया। इंदिरा गांधी ने भी शोले फ़िल्म को तब तक नहीं बनने दिया जब तक गब्बर सिंह पचीस साल का नहीं हो गया, उसने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ दिया और परिवार छोड़, बीहड़ में जा कर रहने लगा। फिर भी इंदिरा गांधी ने गब्बर सिंह की कहानी को, सॉरी शोले की कहानी को कहीं का नहीं छोड़ा। असल कहानी में गब्बर सिंह ठाकुर, वीरू और जय, तीनों को मार कर अपने मोटे वाले साथी के साथ रामगढ़ पर राज करता है। पर इंदिरा गांधी ने ठाकुर और वीरू को जिन्दा रखा और गब्बर सिंह को साथियों सहित गिरफ्तार करवा दिया। यूं तो शोले फ़िल्म के बहुत से डायलॉग फेमस हैं जो लोगों की जुबान पर अभी तक हैं। जैसे, तेरा क्या होगा कालिया, तेरा नाम क्या है बसंती, कुत्ते के आगे मत नाच बसंती, मैंने आपका नमक खाया है सरकार, तो अब गोली भी खा,और भी बहुत सारे। पर एक डायलॉग बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जो गब्बर सिंह बोलता है, कितने आदमी थे? उसका सही उत्तर गब्बर सिंह को अभी तक नहीं मिला। अब जब गब्बर सिंह जेल से बाहर आ गया है तो सरकार जी कितने आदमी थे का सही उत्तर जानने के लिए एसआईआर करवा रहे हैं। इसलिए भी जरूरी है कि संसद में शोले पर बहस हो। संसद में वंदे मातरम पर, शोले फ़िल्म पर और इस तरह के तमाम विषयों पर एक उत्तेजक बहस हो, यह इसलिए जरूरी है जिससे कि चुनावी धांधली, रुपये का गिरना जैसे बेकार के सामयिक विषयों पर बहस न हो पाए और न ही महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यस्था, पर्यावरण जैसे शाश्वत विषयों पर। संसद का सारा समय और जनता का सारा पैसा बेकार के विषयों पर बर्बाद न हो जाये।

कितना अहम पीएम मोदी का तीन देशों का दौरा? अफ्रीका में व्यापारिक समझौते, पश्चिम एशियाई देश में FTA का मौका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार (15 दिसंबर) को तीन देशों के दौरे पर रवाना हो गए। अपने इस दौरे के जरिए पीएम पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका तक भारत के हितों को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी के दौरे का पहला पड़ाव होगा जॉर्डन, जहां वे दोनों देशों के रिश्ते पूरे होने के 75 वर्षों के जश्न में शामिल होंगे। यहां से इथियोपिया और उसके बाद ओमान में भारत के लिए संभावनाएं तलाशने के बाद 18 दिसंबर को पीएम भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर पीएम मोदी का यह दौरा कितना अहम है? प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं, उन देशों का भारत के लिए और भारत का उनके लिए क्या महत्व है? इन तीनों ही देशों से भारत क्या हासिल कर सकता है? आइये जानते हैं...

कितना अहम है पीएम मोदी का जॉर्डन दौरा?

प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन देशों के दौरे की शुरुआत जॉर्डन से करेंगे। यह उनकी इस पश्चिम एशियाई देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। पीएम मोदी जॉर्डन के शाह किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के निमंत्रण पर 15-16 दिसंबर को यहां रहेंगे। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन पहुंचकर वहां के शाह अब्दुल्ला-II से मुलाकात करेंगे और भारत-जॉर्डन संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों ही नेता क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। बातचीत में आतंकवाद-रोधी सहयोग, ऊर्जा साझेदारी और पश्चिम एशिया में बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच उभरते आर्थिक मौकों पर भी चर्चा होने की संभावना है। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और जॉर्डन अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इस दौरान दोनों नेता भारत-जॉर्डन के बीच व्यापार बढ़ाने से जुड़े कार्यक्रम को भी संबोधित कर सकते हैं।

भारत और जॉर्डन के बीच मजबूत हैं आर्थिक संबंध

विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और जॉर्डन के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं।

भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 2.8 अरब डॉलर है। हाल के समय में जॉर्डन ने भारत के साथ संपर्क भी बढ़ाया है। रॉयल जॉर्डेनियन एयरलाइंस ने अम्मान और मुंबई के बीच सीधी उड़ानें शुरू की हैं और नई दिल्ली के लिए सेवाओं के विस्तार की योजना है।

जॉर्डन भारतीय पर्यटकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी प्रदान करता है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी संवाद करेंगे। अम्मान स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, जॉर्डन में लगभग 17,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से कई कपड़ा उद्योग में काम करते हैं। ऐसे में पीएम मोदी की इस यात्रा का मकसद भारत-जॉर्डन द्विपक्षीय जुड़ाव को और मजबूत करना, पारस्परिक विकास और समृद्धि के लिए सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश करना और क्षेत्रीय शांति, समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दोहराना है।

भारत के लिए इथियोपिया क्यों महत्वपूर्ण?

जॉर्डन के बाद प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीकी महाद्वीप में भारत के हितों को आगे रखेंगे। 16 दिसंबर को वे इथियोपिया पहुंचेंगे। यह उनका पहला इथियोपिया दौरा होगा। यहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली के साथ व्यापार बढ़ाने को लेकर चर्चा करेंगे। खासकर कुछ अहम क्षेत्र, जैसे- कृषि, निवेश और विकास साझेदारी के क्षेत्रों में। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानेसबर्ग में वार्ता हुई थी।

यह मुलाकात ब्रिक्स सम्मेलन से इतर हुई थी, जिसका इथियोपिया बाद में सदस्य बना है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इथियोपिया वैश्विक दक्षिण और अफ्रीका में एक अहम देश है। ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा भारत का दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए प्रतिबद्धता दर्शाता है। भारत-इथियोपिया शिक्षा, कौशल और क्षमता विकास के कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। भारत ने इथियोपिया के छात्रों और पेशेवरों को शिक्षा के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल किया है।

साथ ही स्टूडेंट्स के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं भी तैयार की हैं बता दें कि पीएम मोदी इस साल तीसरी बार अफ्रीकी महाद्वीप पर जा रहे हैं। इसे एशिया के बाहर भारत का वर्चस्व बढ़ाने के अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। भारत पूर्व अफ्रीका में स्थित इस देश के शीर्ष तीन निवेशक देशों में से भी है। भारत ने इथियोपिया में कृषि, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, उत्पादन, कपास और कपड़ा उद्योग में निवेश किया है। इतना ही नहीं भारत की 650 कंपनियों का इथियोपिया में पांच अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश है।

क्या रहेगा पीएम मोदी के इथियोपिया दौरे का एजेंडा?

प्रधानमंत्री के दौरे पर भारत और इथियोपिया के बीच व्यापार पर चर्चा प्रमुख होगी। इथियोपिया के लिए भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो कि इस देश के लिए भारत के महत्व को काफी बढ़ा देता है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देशों के बीच 2023-24 में 57.15 करोड़ डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए भारत अब इथियोपिया में इन्फ्रास्ट्रक्चर, आईटी, खनन, कृषि और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर जोर देगा। पीएम मोदी इथियोपिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इथियोपिया के शिक्षा क्षेत्र में भारतीयों की अच्छी-खासी मौजूदगी है। अलग-अलग विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में 150 से ज्यादा भारतीय फैकल्टी में जुड़े हैं। इसके अलावा अफ्रीका की बात करें तो यहां इथियोपिया सबसे कम दर पर लंबी अवधि का कर्ज पाने वाला देश है। भारत ने इथियोपिया के अलग-अलग सेक्टर्स को एक अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज दिया है। इथियोपिया से रवाना होने से पहले भारतीय प्रधानमंत्री यहां संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे।

दौरे का आखिरी पड़ाव- ओमान, जहां भारत को मिल सकता है एफटीए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का आखिरी पड़ाव ओमान होगा। दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 17 से 18 दिसंबर तक ओमान जाएंगे। यह उनकी ओमान की दूसरी यात्रा होगी। भारत और ओमान के कूटनीतिक संबंधों के 70 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर खास ध्यान रहेगा। माना जा रहा है कि यह समझौता दोनों देशों के व्यापार और निवेश को नई दिशा देगा। पीएम मोदी अपने साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर ओमान पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि यहां दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) हो सकता है। इसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) कहा जा रहा है। इसे लेकर भारत-ओमान के बीच नवंबर 2023 से ही बातचीत जारी थी और इस साल इसे लेकर दोनों में सहमति भी बन गई। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम मोदी के ओमान दौरे से पहले ही एफटीए को मंजूरी दे दी। दूसरी तरफ ओमान की शूरा परिषद, जिसे सबसे निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था कहा जाता है, ने भी समझौते को हरी झंडी दिखाई है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी ओमान पहुंचेंगे तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी समझौते पर हस्ताक्षर के लिए उनके साथ मौजूद रह सकते हैं।

कितने मजबूत हैं भारत-ओमान के व्यापारिक रिश्ते?

पीएम मोदी के दौरे का मुख्य मकसद भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करना है। इसमें आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी पर विशेष जोर दिया जाएगा। खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य ओमान ही है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत-ओमान द्विपक्षीय व्यापार 10.61 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को दर्शाता है। भारत का इसी तरह का मुफ्त व्यापार समझौता (एफटीए) मई 2022 से जीसीसी के एक अन्य सदस्य देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ लागू है।

रक्षा क्षेत्र में और गहरे हो सकते हैं रिश्ते

भारत और ओमान द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इस कड़ी में मस्कट ने भारत को रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए जगुआर लड़ाकू विमानों के स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने की पेशकश की है। ओमान की वायुसेना ने अपने जगुआर विमानों को सेवा से हटा दिया है और उनके स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति जल्द होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय में सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने पीएम मोदी के दौरे से पहले कहा था, रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान पहले जगुआर जेट का संचालन करती थी, लेकिन उन्हें कुछ समय पहले सेवा से हटा लिया गया। उनके पास इन विमानों के कई स्पेयर पार्ट्स हैं, जिन्हें वे भविष्य में भारत को सौंपने के लिए तैयार हैं और हमें उम्मीद है कि इन स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगी। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे करीबी रक्षा साझेदार माना जाता है। रक्षा सहयोग दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी का अहम हिस्सा बन चुका है। ओमान पहला खाड़ी देश है जिसके साथ भारत की तीनों सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास करती हैं। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि भारत और ओमान के बीच हाइड्रोकार्बन सहयोग आगे भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ओमान यात्रा के दौरान रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, खाद्य सुरक्षा और संपर्क जैसे विषयों पर चर्चा प्रमुख एजेंडा में शामिल होंगे। संभावित एफटीए की घोषणा से भारत-ओमान संबंधों को और नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है।

'हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना-2025' 17 दिसम्बर तक भेजे जा सकेंगे नाम

चंडीगढ़।

हरियाणा सरकार ने अपने अभिनव कार्यों और असाधारण प्रयासों से बेहतर शासन में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 'हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना, 2025' के लिए आवेदन मांगे हैं। सुशासन पुरस्कारों के आवेदन करने या नाम भेजने की तिथि बढ़ाकर 17 दिसम्बर, 2025 कर दी गई है। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएगा। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में सभी प्रशासकीय सचिवों को सभी राज्य स्तरीय पुरस्कारों (राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार और राज्य पुरस्कार) के लिए अनुशंसा अपनी टिप्पणी के साथ अपलोड करने के लिए कहा गया है। राज्य फ्लैगशिप पुरस्कारों के अंतर्गत अधिकतम पांच पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पुरस्कार में एक ट्रॉफी, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा नकद पुरस्कार शामिल होगा। प्रशस्ति पत्र की एक प्रति संबंधित प्रशासनिक सचिव के माध्यम से कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखी जा सकती है। प्रत्येक फ्लैगशिप पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को 51,000 की नकद राशि प्रदान की जाएगी। यदि पुरस्कार किसी समूह को दिया जाता है, तो समूह में अधिकतम चार सदस्य होंगे तथा सभी सदस्यों को पद या स्तर की परवाह किए बिना समान राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर अधिकतम पांच राज्य पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक राज्य पुरस्कार में एक ट्रॉफी, मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा प्रति सदस्य 51,000 की नकद राशि शामिल होगी। समूह को दिए जाने वाले पुरस्कारों में भी अधिकतम चार सदस्य होंगे और सभी सदस्यों को समान राशि प्रदान की जाएगी। जिला स्तर पर सुशासन पुरस्कार प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर उपायुक्त द्वारा प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में अधिकतम पांच जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जा सकेंगे। प्रत्येक जिला स्तरीय पुरस्कार में एक ट्रॉफी, संबंधित मंडल के मंडलायुक्त द्वारा उपायुक्त की संस्तुति पर हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा प्रति सदस्य 31,000 की नकद राशि शामिल होगी। प्रशस्ति पत्र की एक प्रति उपायुक्त के माध्यम से कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखी जा सकती है। समूह पुरस्कारों के लिए अधिकतम चार सदस्यों की संख्या निर्धारित होगी और सभी सदस्यों को समान राशि प्रदान की जाएगी। ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र का खर्च वहन उपायुक्त द्वारा अपने उपलब्ध बजट से किया जाएगा, जबकि नकद पुरस्कार राशि की प्रतिपूर्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित उपायुक्त को की जाएगी। राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन एवं नामांकन सशक्त समिति द्वारा संबंधित प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसंधान इकाई) में प्राप्त किए जाएंगे। सशक्त समिति अपने विवेक से किसी योजना को भी स्वतः चयन हेतु चिन्हित कर सकती है। प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्षों से परामर्श के उपरांत, राज्य स्तरीय पुरस्कार-राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार के लिए अधिकतम चार कर्मचारियों के नामों की संस्तुति कर सकेंगे। एक बार किसी योजना को पुरस्कार दिए जाने के पश्चात वह आगामी वर्षों में पुनर्विचार के लिए पात्र नहीं होगी। जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए, आवेदन एवं नामांकन जिला स्तरीय सशक्त समिति द्वारा संबंधित जिले के जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुखों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। किसी योजना को यदि एक बार जिला स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, तो वह आगामी वर्षों में पुनः विचार के लिए पात्र नहीं होगी।

सभी आवेदन एवं नामांकन अनिवार्य रूप से विभागाध्यक्षों एवं संबंधित प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से ही भेजे जाएंगे। व्यक्तिगत कर्मचारी या अधिकतम चार सदस्यों का समूह राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए अपने आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। विभागाध्यक्ष अपनी विस्तृत टिप्पणी के साथ आवेदन को प्रशासनिक सचिव को भेजेंगे, जो अपनी टिप्पणी के साथ इसे सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसंधान इकाई) को भेजेंगे। प्रशासनिक सचिव उचित कारणों सहित स्वतः नामांकन भी कर सकते हैं। सशक्त समिति को सीधे भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इन पुरस्कारों के लिए प्रदर्शन की प्रासंगिक अवधि 1 जनवरी, 2024 से 30 अक्टूबर, 2025 तक निर्धारित की गई है। आवेदन पर विचार किए जाने के लिए haryana-goodgovernanceawards.haryana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु प्रशासनिक सचिवों से प्राप्त सभी नामांकनों को सशक्त समिति के समक्ष संस्तुति के लिए प्रस्तुत करेगा। राज्य स्तरीय पुरस्कारों के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी हरियाणा सरकार होगी, जबकि जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त सक्षम प्राधिकारी होंगे।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घाटी ने करन ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पीतमपुरा एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार घाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/08862)

मुरादाबाद बंद में सहयोग के लिये व्यापारियों से किया जन सम्पर्क

मुरादाबाद। दि बार एसोसिएशन एण्ड लाईब्रेरी मुरादाबाद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश खण्डपीठ समिति के आव्हान पर 17 दिसम्बर को मुरादाबाद बंद का आव्हान किया और राजकीय इंटर कालेज से कलेक्ट्रेट तक हाईकोर्ट बैंच की मांग को लेकर प्रदर्शन मार्च निकाला जायेगा। इस सम्बन्ध में आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनन्द मोहन गुप्ता, महासचिव कपिल गुप्ता के नेतृत्व में 17 दिसम्बर को बंद करने हेतु कचहरी से कोर्ट रोड, ताड़ीखाना चौक, गुलज़ारीलाल की धर्मशाला रोड से बुद्ध बाजार , टाउनहाउस, बाजार गंज के व्यापारियों से आग्रह किया। व्यापारियों ने भी सस्ता और सुलभ न्याय हेतु हाईकोर्ट बैंच की स्थापना के लिये सहयोग का आश्वासन दिया। जन सम्पर्क में अध्यक्ष आनन्द मोहन गुप्ता, महासचिव कपिल गुप्ता, कोषाध्यक्ष बंसल, आवरण अग्रवाल, रमेश सिंह आर्य,पुनीत चौहान, राजेश कुमार, जेपी सिंह, पुष्प यादव आशीष उपाध्याय, आशीष त्रिवेदी, संतोष कुमार सिंह इकबाल हुसैन जब्बार हुसैन आदि रहे।

हाईकोर्ट बैंच के लिए भारत रक्षा सेना ने दिया समर्थन

मुरादाबाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बैंच स्थापना के लिए चलाये जा रहे आन्दोलन के लिए भारत रक्षा नेता ने दि बार एसोसिएशन एवं लाइब्रेरी को अपने समर्थन का ऐलान किया है। भारत रक्षा सेना के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेन्द्र यादव ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आम जनता को सस्ता सुलभ व त्वरित न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट बेंच बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट बैंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे हाईकोर्ट बैंच की शीघ्र स्थापना के लिए 17 दिसम्बर को मुरादाबाद बंद का भारत रक्षा सेना समर्थन करती है। साथ ही आंदोलन मे बढ़ चढ़ का भागेदारी करने का भरोसा दिलाती है एवं सभी संगठन के पदाधिकारी इस आंदोलन में सक्रिय भागेदारी करेंगे।

एनएसओ ने किया सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन

मुरादाबाद। नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन (एनएसओ) ने आज अपने प्रधान कार्यालय स्थित व्हाइट हाउस गुजराती स्ट्रीट में एक हिन्दी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा की सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें संस्था की कार्यकारिणी के अनेक पदाधिकारियों के कक्षा तीन, चार व पाँच के ब'चों ने भाग लिया। इस सुलेख प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार कक्षा तीन के लिए हानिया व अशहर, कक्षा चार के लिए हेनुफ व नबीह तथा कक्षा पाँच हेतु कुलसूम आरिफ ने प्राप्त किये एवं शेष प्रतिभागियों को भी प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये गये। अंत में परीक्षक के रूप में शामिल मसर्रत हफीज महासचिव एनएसओ तथा अध्यक्ष मिर्जा अरशद बेग ने बचों को दुआये व उनके पिता व अभिभावकों को बधाई दी।

बनारस रवाना हुआ युवाओं का दल

मुरादाबाद।

मेरा युवा भारत का जिला युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 35 युवाओं का दल बनारस के लिए रवाना। उप निदेशक अंकित कुमार गौर ने बताया की हमारे प्रतिभागी 15 दिसंबर से 19 दिसंबर के दौरान बनारस में रहेंगे इस दौरान उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा साथ-साथ उन्हें संस्कृत खेलकूद आदि गतिविधियों में प्रतिभा करने का अवसर मिलेगा उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिभागियों को बनारस स्थानीय संस्कृति पर्यटक स्थल दिखाए जाएंगे एवं सामान्य अगले सप्ताह 35 प्रतिभागी जनपद बनारस से मुरादाबाद आएंगे अंकित कुमार गौर ने बताया की इसी तरह बनारस से आने वाले प्रतिभागियों को जनपद मुरादाबाद का भ्रमण करवाया जाएगा यह विशेष कार्यक्रम की श्रेणी में आयोजित किया जा रहा कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न जनपदों की संस्कृत विरासत भाषा एवं स्थानीय व्यंजन से परिचित करवाना है इन शामिल प्रतिभागियों में सभी प्रतिभागी युवावस्था के हैं एवं यह सभी संपूर्ण जनपद के आठ विकास खण्ड से आए हैं मुरादाबाद परिवहन निगम की बस में सवार होकर सभी प्रतिभागी काशी नगरी बनारस के लिए रवाना हुए इस कार्यक्रम में रंजीत कुमार सैनी एवं चंद्र सिंह अनुरक्षण के तौर पर जा रहे हैं।

मेरा युवा भारत का युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम

चार रायों में दबिश, 300 लोगों से पूछताछ, दो भाइयों के हत्यारे अब तक फरार

संभल। दो सगे भाइयों की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस और एसओजी की टीमें हत्यारों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। चार रायों में दबिश के साथ ही अब तक 300 से यादा लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है लेकिन हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बहजोई क्षेत्र के गांव मैथरा धर्मपुर निवासी अमरपाल (14) और कमल सिंह (10), पुत्र रामौतार 26 नवंबर को अपने ननिहाल तहसील गुन्नौर में थाना धनारी क्षेत्र के गांव मझोला से बरात में शामिल होने के लिए अन्य बरातियों के साथ पिकअप पर सवार होकर रवाना हुए थे।

घने कोहरे ने प्रभावित किया जन जीवन

मुरादाबाद। महानगर में सोमवार को घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन प्रभावित किया। सुबह शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। घने कोहरे के कारण सड़कों पर विज़िबिलिटी बेहद कम हो गई। हाईवे और मुख्य मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई, और वाहन चालकों को हेडलाइट्स जलाकर चलना पड़ा। इससे आवागमन में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।कोहरे के साथ-साथ न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे कड़ाके की ठंड महसूस हुई। सुबह करीब आठ बजे तक सूरज के दर्शन नहीं हुए, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने बताया कि लगातार बढ़ती ठंड और घना कोहरा उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है। मौसम में आए इस बदलाव से मुरादाबाद में अब ठंड का असर साफ दिखाई देने लगा है।

डायट में साइबर सुरक्षा क्विज का धमाल, 'दि बॉयस' बने विजेता

फतेहपुर।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत प्रोग्राम एवं एक्टिविटीज मद से डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 'क्विज-2025' का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय साइबर सुरक्षा रहा, जिसमें प्रशिक्षुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में आदर्श आर्या के नेतृत्व में टीम 'दि बॉयस' ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पुनीत सिंह के निर्देशन में टीम 'दि ट्रॉजन हॉर्स' द्वितीय तथा श्रद्धा देवी के नेतृत्व में टीम 'दि वेब' तृतीय स्थान पर रही। टीम 'दि बॉयस' में धनंजय सोनी, आदर्श आर्या, सुमित कुमार मिश्र, सचिन कुमार और विशेष कुमार शामिल रहे।

टीम 'दि ट्रॉजन हॉर्स' में पुनीत सिंह, आकृति भारती, मुकेश प्रताप, विदुषी पटेल और हर्ष वर्मा रहे, जबकि टीम 'दि वेब' में श्रद्धा देवी, शीरीन नाज हन्नाफ़ी, योति, जाह्नवी साहू और मानसी द्विवेदी शामिल रहीं। सभी विजेता प्रशिक्षुओं को प्राचार्य डायट आरती गुप्ता ने प्रमाणपत्र एवं शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा आज का वलंत और अत्यंत प्रासंगिक विषय है, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसी प्रतियोगिताएं प्रशिक्षुओं में समसामयिक मुद्दों की समझ विकसित करने में सहायक हैं। यह आयोजन राय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ के निर्देशानुसार किया गया। प्रतियोगिता का मूल्यांकन पांच राउंड में हुआ। प्रत्येक सही उत्तर पर दो अंक, गलत उत्तर पर शून्य अंक तथा ओपन टू ऑल प्रश्न का सही उत्तर देने पर एक बोनस अंक दिया गया। प्रतिभागियों ने हैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, वायरस, रैनसमवेयर, स्पाइवेयर, फिशिंग और साइबर बिलिंग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दिए। कार्यक्रम के नोडल व निर्णायक मंडल में प्रवक्ता अमृत कुमार यादव, डाली सिंह और शाइस्ता इकबाल रहीं। स्कोरिंग का कार्य प्रियंका यादव ने तथा सचेतक की भूमिका हिमांशु पटेल ने निभाई। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का संचालन अमृत कुमार यादव ने किया। कार्यक्रम में संस्थान के सभी प्रवक्ता एवं प्रशिक्षु उपस्थित रहे।

खादी प्रदर्शनी का शुभारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा मन

मुरादाबाद।

शहर में साईं मंदिर रोड पर स्थित युवा केंद्र में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा आयोजित मुरादाबाद खादी महोत्सव 2025 का शुभारंभ एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी में गंगा आरोग्य धाम मुरादाबाद के ब'चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। देश के विभिन्न प्रदेशों और जनपदों से आई उत्कृष्ट खादी ग्रामोद्योग इकाइयों का एमएलसी ने भ्रमण किया और इकाइयों द्वारा तैयार किए गए आकर्षक उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की। परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी श्री सत्यवीर सिंह ने बताया कि इस प्रदर्शनी में उत्तराखंड के वूलन, रेडीमेड गारमेंट्स, सहारनपुर का वुडन हैंडीक्राफ्ट, कन्नौज का इत्र, मेरठ का अचार, सिल्क खादी, शहद, जम्मू कश्मीर के वूलन, शॉल एवं सूट, ड्राई फ्रूट, राजस्थान की नमकीन, पंजाब की जूती, भागलपुर की मशहूर खादी, ऑर्गेनिक गुड़ एवं शक्कर, मसालों के साथ-साथ भदोही की कारपेट एवं अन्य आकर्षक उत्पाद उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शनी 24 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी।

चुनाव आयोग पर लगे आरोप की जांच करनी चाहिए थी, बीजेपी तो साथ खड़ी है, क्यों भड़कीं वर्षा गायकवाड़?

नई दिल्ली । नई दिल्ली में 14 दिसंबर को कांग्रेस द्वारा आयोजित बड़ी रैली में बीजेपी, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए गए. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के मुद्दे पर जांच की मांग करने के बजाय भाजपा चुनाव आयोग के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है. इस रैली का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कांग्रेस इसे संसद से सड़क तक लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई बता रही है. नेताओं का दावा है कि जनता अब कथित साजिश को समझने लगी है और इस मुद्दे पर जागरूक हो रही है. कांग्रेस नेता जनार्दन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की बात सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग रैली में पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने हाल के दिनों में भाजपा की कार्यप्रणाली, वोट चोरी और मतदाता सूची में कथित हेरफेर को उजागर किया है, जिससे लोगों को यह समझ आने लगा है कि संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. उनका कहना था कि धन के बल पर वोटरों के अधिकार छीने जा रहे हैं और यह लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा प्रहार है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा और प्रधानमंत्री के दबाव में आकर उसने अपनी निष्पक्षता खो दी है, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक नारों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह भाजपा द्वारा फैलाई गई अफवाह है. उन्होंने स्पष्ट किया कि रैली में वंदे मातरम् और भारत माता की जय जैसे देशभक्ति के नारे लगे. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि संविधान के माध्यम से जनता को वोट का सबसे बड़ा अधिकार दिया गया था और पिछले 70 सालों में सभी सरकारों ने लोकतंत्र की रक्षा में योगदान दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि अब पहली बार लोकतंत्र के किले और वोट चोरी जैसे सवाल उठ रहे हैं. कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि रामलीला मैदान की रैली ने यह संदेश दिया है कि कांग्रेस संविधान को कमजोर नहीं होने देगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा. कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि संसद से लेकर सड़क तक यह आंदोलन जारी है और यदि चुनावी प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ हुआ है तो कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ेगी. उन्होंने कहा कि BJP सत्ता के लिए लड़ती है जबकि कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस राष्ट्रपति को जनता के हस्ताक्षरों के साथ पत्र भेजने की तैयारी कर रही है ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके. वर्षा गायकवाड़ ने सवाल उठाया कि जब चुनाव आयोग पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई जा रही और क्यों भाजपा के मंत्री, सांसद और प्रधानमंत्री इसके समर्थन में खड़े हैं. उन्होंने इसे एक बड़ी साजिश करार दिया. कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह ने कहा कि वोट चोरी देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और लोगों को डर है कि कहीं उनसे मतदान का अधिकार ही न छीन लिया जाए, इसलिए जनता को जागरूक किया जा रहा है और समर्थन भी मिल रहा है.

खत्म होगा मनरेगा

■ ग्रामीण रोजगार पर नया कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार, सांसदों को दी गई प्रस्तावित बिल का कॉपी

नई दिल्ली ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को निरस्त करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। एमजीएनआरईजीए ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। इसके बदले में एक नया कानून - विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) - लाया जाएगा। नए विधेयक में कार्यदिवसों की मौजूदा संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है।

सरकार ने सोमवार को लोकसभा सदस्यों के बीच वह विधेयक प्रसारित किया, जिसका उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। विधेयक की प्रति के अनुसार, इसमें संसद में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (ग्रामीण विकास मिशन) विधेयक, 2025 को प्रस्तुत करने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को निरस्त करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है, जिसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उन सभी ग्रामीण परिवारों को एक सौ पच्चीस दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं; ताकि एक समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति को बढ़ावा दिया जा सके। नया कानून विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करेगा, जिसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक सौ पच्चीस दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं; ताकि एक समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति को बढ़ावा दिया जा सके।

कांग्रेस की रैली में हुआ पीएम मोदी का अपमान! राज्यसभा में नड्डा की मांग, सोनिया गांधी को मांगनी चाहिए माफी

नई दिल्ली ।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पार्टी के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी को कल कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए नारों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। कल की कांग्रेस रैली में पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए। यह कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी बातें कहना निंदनीय है। सोनिया गांधी जी को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। इस बीच, लोकसभा में किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि कांग्रेस की एक रैली में कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाए। उन्होंने इसे भारत के लिए बेहद दुखद समय बताया कि कांग्रेस की पुरानी पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। रिजिजू ने कहा, रैली में कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाए गए। कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने इस टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा कि हमारे राजनीतिक मतभेद भले ही हों, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बारे में बोलते समय हमें संयम बरतना चाहिए। एनसीपी (एसपी) नेता जयंत पाटिल ने कहा कि इस तरह के नारे लगाना सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, वह (नरेंद्र मोदी) प्रधानमंत्री हैं। रविवार को भाजपा पर विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों का विरोध करने के लिए आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के दौरान जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजू लता मीना ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कब्र नारा लगाया। बाद में जब पत्रकारों ने उनसे इस टिप्पणी के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि वह केवल वोट चोरी को लेकर जनता के गुस्से को व्यक्त कर रही थीं। उन्होंने कहा, वह (प्रधानमंत्री मोदी) रोजगार, युवाओं, महिलाओं या किसानों की बात नहीं करते। वह मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। हालांकि, उनकी इस टिप्पणी ने विवाद को जन्म दिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मांग की कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए।

नितिन नबीन पहुंचे भाजपा मुख्यालय, अमित शाह और जेपी नड्डा ने किया भव्य स्वागत

नई दिल्ली । भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के मंत्री नितिन नबीन दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे नितिन नबीन दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां भी उनका भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने नितिन नबीन का अभिनंदन किया। इस अवसर पर नेताओं ने नितिन नबीन के नेतृत्व और संगठन क्षमता की प्रशंसा की और उन्हें पार्टी की नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दीं। नितिन नबीन वर्तमान में बिहार सरकार में पथ निर्माण एवं नगर विकास मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से 2006 के उपचुनाव के बाद से लगातार पांचवीं बार चुनाव जीतकर उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की है। वह कायस्थ समाज से आते हैं और इस समय बिहार मंत्रिमंडल में कायस्थ समाज के इकलौते मंत्री हैं। नितिन नबीन के पिता, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। उनके निधन के बाद नितिन नबीन ने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए पार्टी और जनसेवा में सक्रिय भूमिका निभाई है।

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुंबई से 2 आतंकवादी किए गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से आर्मेनिया से ऑपरेट कर रहे दो आतंकवादियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकवादियों के नाम साजन मसीह और मनीष बेदी बताए गए हैं। जांच में सामने आया है कि ये दोनों आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हरविंदर रिंदा और विदेश से ऑपरेट कर रहे हैप्पी पासियां के लिए काम कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, साजन मसीह और मनीष बेदी दुबई से आर्मेनिया और अन्य देशों के रास्ते मुंबई पहुंचे थे। साजन मसीह गुरदासपुर का रहने वाला है, जबकि मनीष बेदी अमृतसर का निवासी है। ये दोनों आतंकवादी अमृतसर और गुरदासपुर के क्षेत्रों में ग्रेनेड हमले, हत्या, फिरौती और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं।

सीएम नीतीश कुमार ने हटाया महिला का हिजाब, आरजेडी ने बताई दयनीय हालत

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार 15 दिसंबर को 1283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन भी उनके पास नियुक्ति पत्र लेने पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने पहले तो नुसरत परवीन को नियुक्ति पत्र सौंप दिया और फिर उन्हें देखने लगे। डॉक्टर नुसरत भी मुख्यमंत्री को देखकर मुस्कुराईं, इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा कि ये क्या है जी? महिला ने जवाब दिया हिजाब है सर! इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले, हटाइए इसे।

फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ही हाथ आगे बढ़ाकर डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटा दिया। सीएम के ऐसा करने पर डॉ. नुसरत परवीन कुछ देर के लिए असहज दिखीं। इस बीच आसपास मौजूद लोग हंसने लगे। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने महिला डॉक्टर को फिर से से नियुक्ति पत्र थमाया और इसके बाद जाने का इशारा किया। बता दें कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग में हुआ था। इस वीडियो पर प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी ने प्रश्न उठाए हैं। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म x पर लिखा- यह क्या हो गया है नीतीश जी को। मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे उनमें 1283 आयुष डॉक्टरों में से 685 आयुर्वेदिक, 393 होमियोपैथिक और 205 यूनानी डॉक्टर शामिल हैं।

राममंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन

अयोध्या। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संत और पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का 75 वर्ष की आयु में आज सुबह निधन हो गया। वह 10 दिसंबर को दिल्ली से रीवा गए थे, जहां उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। बताया जा रहा है कि रामकथा चल रही थी। इस दौरान उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। बीमार पड़ने के बाद पिछले दो दिनों से उनका वहीं इलाज चल रहा था। सीएम योगी ने रामविलास वेदांती के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ, पूर्व सांसद एवं श्री अयोध्या धाम स्थित वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉ. रामविलास वेदांती जी महाराज का गोलोकगमन आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! उनका जाना एक युग का अवसान है। धर्म, समाज व राष्ट्र की सेवा को समर्पित उनका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त शिष्यों एवं अनुयायियों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आप को बता दें कि रामविलास वेदांती हनुमानगढ़ी के महंत तथा राम मंदिर उद्धारक महंत अभिराम दास के शिष्य रामविलास दास वेदांती हिंदू धाम नया घाट में निवास करते थे।

कोहरे का कहर: एक के बाद एक टकराईं 25 कारें, 4 लोगो की मौत

नूंह । उत्तर भारत के अधिकांश इलाके आज सुबह घने कोहरे में ढंके हुए थे. इस घने कोहरे ने हर तरह के यातायात व्यवस्था को प्रभावित किया. सीजन के इस पहले कोहरे की वजह से सोमवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक-एक करके 25 गाड़ियां टकरा गईं. इन हादसों में चार लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हुए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक इन हादसों के पीछे अमरूद का बड़ा हाथ. एक ट्रक के पलट जाने से उस पर लदा अमरूद सड़क पर फैल गया. मिली जानकारी के मुताबिक सीजन के पहले घने कोहरे के कारण सोमवार तड़के करीब पांच बजे ये हादसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए. घने कोहरे की वजह से एक्सप्रेस वे पर दृश्यता बेहद कम थी. इस वजह से एक के बाद एक करीब 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस दर्दनाक हादसे में दो पुलिसकर्मियों समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इन हादसों में करीब 20 लोगों के गंभीर रूप से घायल हो गए. प्राप्त जानकारी के मुताबिक हादसे की शुरुआत दो ओवरलोड डंपरों की आपसी टक्कर से हुई. टक्कर के तुरंत बाद पीछे से आ रहा अमरूद से भरा एक ट्रक भी इन वाहनों से जा भिड़ा. ट्रक के पलटते ही सड़क पर बड़ी मात्रा में अमरूद फैल गए. इससे वहां फिसलन और अफरा-तफरी मच गई. कोहरे और सड़क पर फैले फलों के कारण पीछे से आने वाले वाहन समय पर ब्रेक नहीं लगा सके. इससे लगातार कई गाड़ियां इस हादसे का शिकार हो गईं.

सीएम विंडो की हर शिकायत जनता के विश्वास का प्रतीक, इसे जीवंत दस्तावेज मानकर हो ईमानदार समाधान- मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ ।

प्रबुद्धजन पारदर्शिता व संवेदनशीलता के साथ निभाएं अपनी अहम जिम्मेदारी

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सीएम विंडो पर दर्ज होने वाली प्रत्येक शिकायत केवल एक औपचारिक प्रविष्टि नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का जीवंत दस्तावेज है।

इससे जुड़े प्रबुद्धजनों की जिम्मेदारी है कि वे इन शिकायतों को पूरी ईमानदारी, विश्वास और पारदर्शिता के साथ देखकर उनके समाधान में सक्रिय योगदान दें। चूंकि ये प्रबुद्धजन सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हैं, इसलिए जनता के प्रति उनकी जवाबदेही और भी अधिक बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री सोमवार को अपने निवास स्थान 'संत कबीर कुटीर' में प्रदेश के सभी जिलों से आए सीएम विंडो से जुड़े प्रबुद्धजनों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर सीएम विंडो को ऐसा सशक्त और भरोसेमंद सिस्टम बनाना है, जिस पर हर नागरिक को गर्व हो और उसे यह विश्वास हो कि उसकी शिकायत का समयबद्ध और प्रभावी समाधान निश्चित रूप से होगा।

इस विश्वास के कायम रहने से प्रशासनिक तंत्र भी और अधिक निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से 25 दिसंबर, 2014 को सीएम विंडो पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अब तक इस पोर्टल पर कुल 14 लाख 82 हजार 924 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 14 लाख 12 हजार 136 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनसमस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि जब कोई नागरिक सीएम विंडो पर अपनी समस्या दर्ज करता है, तो वह केवल शिकायत नहीं लिखता, बल्कि अपने मुख्यमंत्री और सरकार पर भरोसा जताता है। इसलिए इस मजबूत मंच का पारदर्शी और संवेदनशील होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनता का यह भरोसा और अधिक सुदृढ़ हो सके। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जिला स्तर पर शिकायतों के प्रभावी निपटारे के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार और वीरवार को समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेशभर में आयोजित इन शिविरों में अब तक 1 लाख 47 हजार 299 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1 लाख 19 हजार 597 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि शेष शिकायतों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों से आह्वान किया कि वे प्रत्येक शिकायत की गहन जांच करें और निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से समाधान सुनिश्चित कर शिकायतकर्ता का विश्वास जीतें। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती, प्रदेश महामंत्री डॉ. अर्चना गुप्ता, महामंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।

हर जरूरतमंद की सेवा ही सरकार का लक्ष्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य ''हर जरूरतमंद की सेवा करना'' है। योगी आदित्यनाथ ने यहां 'जनता दर्शन' के दौरान यह बात कही। 'जनता दर्शन' के दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए प्रत्येक फरियादी से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं और सभी के प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्त एवं उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। एक बयान के अनुसार, 'जनता दर्शन' में प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) के एक सिपाही ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्या से अवगत कराया जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए मामले के उचित निस्तारण का निर्देश दिया। शाहजहांपुर से आए एक किसान ने धान खरीद केंद्रों पर लापरवाही की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, ''सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार कार्य कर रही है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।'' मुख्यमंत्री ने शाहजहांपुर के जिलाधिकारी को खरीद केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। प्रयागराज से भी कुछ फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित मामलों में प्रयागराज के जिला एवं पुलिस प्रशासन को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''हर जरूरतमंद की सेवा ही सरकार का लक्ष्य है। सरकार पहले दिन से ही जनता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले साढ़े आठ वर्षों से सरकार जनता की समस्याएं सुनने और उनके समाधान के लिए नियमित रूप से कार्य कर रही है।'' उन्होंने 'जनता दर्शन' में आए लोगों को आश्वस्त किया कि हर समस्या का उचित और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

कब्र खुदेगी वाले बयान पर हंगामा? प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा- महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से भाग रही सरकार

नई दिल्ली । कांग्रेस की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को सवाल उठाया कि इस मुद्दे को संसद में क्यों उठाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय संसदीय मंत्री कार्यवाही में बाधा डाल रहे थे और सत्ताधारी दल प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को रोक रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आप (मीडिया) यह नहीं पूछते कि केंद्रीय संसदीय मंत्री स्वयं सदन की कार्यवाही में बाधा क्यों डाल रहे थे... मंच से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि फिर हमें पता चला कि जनता में से किसी व्यक्ति या कार्यकर्ता ने ऐसा बयान दिया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह कौन था। तो फिर इस मामले को सदन में क्यों उठाया जा रहा है? वे (सत्ताधारी दल) सदन को चलने ही नहीं देना चाहते। हमने प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन वे वह भी नहीं कर रहे हैं। उनकी ये टिप्पणी कांग्रेस नेता मंजू लता मीना के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कथित वोट चोरी के विरोध में पार्टी द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान कथित तौर पर कहा था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मीना ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि वह केवल कथित वोट धांधली पर जनता के गुस्से को व्यक्त कर रही थीं और प्रधानमंत्री पर प्रमुख मुद्दों को हल करने में विफल रहने का आरोप लगा रही थीं। उन्होंने कहा कि मतदान में धांधली को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। उन्होंने (भाजपा ने) धांधली करके सरकारें बनाई हैं और चुनाव आयोग भी उनके निर्देशों पर काम कर रहा है। वह (प्रधानमंत्री मोदी) रोजगार, युवाओं, महिलाओं या किसानों की बात नहीं करते। वह मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, मीना ने कहा। वह जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी हैं। दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण की स्थिति पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसदीय चर्चा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, स्थिति पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गई है। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं इस पर चर्चा के लिए एक नोटिस जारी करूंगी।